"शराब पिएं और पिलाएं ! अशिक्षा को दूर भगाएं !!"

मेरे एक भाई साहब हैं। एक सरकारी विद्यालय में अध्यापक हैं। नैनीताल में ही एक ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं। कहने लगे कि क्या जमाना आ गया है, मेरा एक 'कुलीग' मुरादाबाद से शराब के पाउच स्मगल करके लाता है और विद्यालय की आड़ में ग्रामीणों को शराब सप्लाई करता है। वैसे भी पहाड़ में शराब और शिक्षा दो महत्वपूर्ण समस्याएं रही हैं। शराब बन्दी को लेकर आन्दोलन तक होते रहते हैं। भाई साहब ने कहा कि अगर एक शिक्षक ही अवैध शराब का कारोबार करेगा तो फिर वह बच्चों को शिक्षा क्या देगा ?

बात मार्के की है। लेकिन उन्हें शायद यह नहीं पता कि शिक्षा और शराब का कितना जीवंत रिश्ता है। इसे पंजाब की राज्य सरकार ने बखूबी पहचाना है। शराब की सर्वाधिक खपत वाले राज्य पंजाब ने शराब से शिक्षा देने का अचूक नुस्खा ढूंढ निकाला है और उस पर वह अमल भी कर रही है। आप जितना शराब पीयोगे, बच्चे उतनी अच्छी तालीम पायेंगे। आप कहोगे कि क्या बेवकूफी की बातें हैं ?

भाई मेरे, आप इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर रहे हो, क्या कुछ संभव नहीं है ! बस पहल लेने की जरूरत है ! पंजाब सरकार ने एक पहल ली है। अब सभी राज्य सरकारों को, यहां तक कि केन्द्र सरकार को भी इससे सीख लेनी चाहिए !

हुआ यह है कि पंजाब की राज्य सरकार के एक निर्णय के तहत पंजाब में बिकने वाली शराब की प्रत्येक बोतल पर पांच रुपये शिक्षा अधिभार लगाया गया है। इससे प्राप्त धनराशि राज्य में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति सुधारने पर खर्च होगी। वैसे भी, पंजाब सरकार का यह कोई नया करिश्मा नहीं है। यहां पहले शराब की एक बोतल पर एक रुपये शिक्षा अधिभार लिया जाता था। लेकिन यह आमदनी पर्याप्त न होने के कारण इसे अब पांच रुपये कर दिया गया।

अब अगर भाई साहब पंजाब में होते तो अपने सहयोगी शिक्षक के कार्यों के आलोचक नहीं, प्रशंसक ही होते ! पंजाब सरकार ने उन तमाम आलोचकों की बात का माकूल जवाब दे दिया जो कहते हैं कि शराब से घर-परिवार बर्बाद हो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई सब बर्बाद हो जाती है। वैसे शराबी तो तर्कों की खाक परवाह भी नहीं करते। पर सरकार को तो तर्क भी चाहिए और पैसा भी ! हरियाणा व आंध्र में शराबबन्दी के बाद राजस्व घट गया प्रदेश में आर्थिक संकट आ गया। पर पंजाब सरकार 'टेंशन फ्री' हो गयी क्योंकि उसके पास 'रामबाण' तर्क मौजूद है कि अगर लोग शराब नहीं पियेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे ?

दरअसल बात यह है कि हमारे देश में सरकारें "अच्छे" प्रयोगों की ओर ध्यान ही नहीं देतीं। अब अगर उत्तर प्रदेश सरकार भी यही योजना लागू कर ले तो हो जाए पांचों अंगुली घी में। बल्कि हम तो यह कहते है कि हमारी सरकार को इस आविष्कार को और आगे बढ़ाना चाहिए। उसे शिक्षा को शराब कम्पनियों द्वारा प्रायोजित करवाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों और स्कूल ड्रेसों तक में शराब कम्पनी के प्रतीक चिह्न लगाने चाहिए। बल्कि कुछ शराब की बोतलें व रेट लिस्ट भी छात्रों में प्रचार के लिए बांटी जानी चाहिए। जिनमें यह लिखा हो कि "शराब पियें और पिलाएं अशिक्षा को दूर भगाएं" या फिर "पियो और पढ़ाओ, भारत को साक्षर बनाओ" आदि-आदि।

हो सकता है कि कोई आलोचक महोदय कहें कि इससे बच्चों में भी दारू पीने की लत पड़ सकती है। कौन समझाये इन आलोचकों को, कि इससे भी होगा तो लाभ ही। बच्चे अपने पढ़ने का कुछ खर्चा खुद भी उठायेंगे। उनमें स्वावलम्बन की भावना जागृत होगी।

● चारुचन्द्र

... बोलते आंकड़े ...
... चीखती सच्चाइयां ...

☞ विश्व स्तर पर आधा पेट खाने की मजबूरी के साथ सोने वालों की आधी संख्या एशिया में रहती है।

☞ खाद्य एवं कृषि संगठन के ताजा आंकड़ों के अनुसार विश्व के दो तिहाई युवा उन देशों में रह रहे है जहां प्रति व्यक्ति सालाना आय 50 हजार रुपये से भी कम है। जबकि 12 प्रतिशत युवा ही शानो-शौकत वाले अमीर देशों में जी रहे हैं।

☞ इस समय देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के 10 हजार मैनेजर ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपये से भी ज्यादा है, जबकि 60 प्रतिशत आबादी ऐसी है जिन्हें पांच हजार रुपये वार्षिक आय से भी कम में गुजारा करना पड़ता है। याने एक अनुपाते एक हजार का अन्तर है। उदारीकरण की नीतियों के लागू होने के बाद से देश में अमीरी-गरीबी की खाई बेइन्तहां बढ़ने का यह एक उदाहरण मात्र है।

☞ एक परमाणु बम बनाने में होने वाले 4 करोड़ रुपये खर्च से गरीब आबादी के लिए 3300 मकान बनाये जा सकते थें, एक अग्नि मिसाइल की निर्माण लागत 60 करोड़ रुपये से 15 हजार ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों का सालाना खर्च चल सकता है।

☞ वर्ष 1999-2000 का केन्द्रीय वार्षिक रक्षा बजट 45 हजार करोड़ रुपये है। रक्षा मंत्रालय के नियमित प्रशासनिक और पेंशन खर्चों को जोड़कर यह 55 हजार करोड़ रुपये होगा। अगर मौजूदा रक्षा बजट, जो सकल घरेलू उत्पाद का 2-3 प्रतिशत है और जो कारगिल युद्ध के बाद बढ़कर 3-5 प्रतिशत तक (अनुमानित) पहुंच गया, तो कुल वास्तविक रक्षा बजट होगा 70-75 हजार करोड़ रुपये, जो सरकार के कुल सालाना व्यय के 25 प्रतिशत से भी ज्यादा होगा।